दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-२ ला | अंक-६३ वा | रविवार ७ दिसंबर २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

आठवें वेतन आयोग: प्रमोशन और वेतन वृद्धि के लिए परीक्षा अनिवार्य? कर्मयोगी पोर्टल पर कोर्स और मूल्यांकन की नई शर्तें

नई दिल्ली, ६ दिसंबर २०२५ (स्पेशल रिपोर्ट)

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) के तहत वेतन संरचना में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है, जिसमें प्रमोशन और सालाना वेतन वृद्धि के लिए कर्मयोगी (ळऋजढ) पोर्टल पर अनिवार्य कोर्स पूरे करने और परीक्षा पास करने की नई शर्तें प्रस्तावित हैं। यह बदलाव सरकारी तंत्र को अधिक कुशल और प्रदर्शन-आधारित बनाने का प्रयास है, लेकिन कर्मचारी संगठनों में इससे असंतोष भी पैदा हो रहा है। आयोग का गठन जनवरी २०२५ में हो चुका है और इसकी सिफारिशें १ जनवरी २०२६ से लागू होने की संभावना है।

आठवें वेतन आयोग का बैकग्राउंड और हालिया अपडेट

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने १६ जनवरी २०२५ को आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, जो लगभग ५० लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और ६५ लाख पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में संशोधन करेगा। नवंबर २०२५ में आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें १८ महीनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने का लक्ष्य रखा गया है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने २८ अक्टूबर २०२५ को इसकी मंजूरी दी, जो सातवें वेतन आयोग (२०१६) के बाद १० साल बाद आ रहा है।

आयोग का मुख्य उद्देश्य वेतन मैट्रिक्स को अपडेट करना, महंगाई भत्ता (D-) को बेसिक पे में मर्ज करने पर विचार करना और प्रदर्शन से जुड़ी वेतन वृद्धि (झशीषीारपलश-डळपज्ञशव झरू) को मजबूत करना है।श वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पुष्टि की है कि ऊ- को बेसिक पे में मर्ज करने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर (वेतन गुणक) को २.८६ से बढ़ाकर ३.० तक ले जाने पर चर्चा हो रही है।रश६शषल

वेतन वृद्धि की उम्मीदें: कितना बढ़ेगा सैलरी?

विशेषज्ञों के अनुसार, आठवें वेतन आयोग से औसतन २५-३५% की वेतन वृद्धि हो सकती है। न्यूनतम बेसिक सैलरी

वर्तमान १८,००० रुपये से बढ़कर ५०,०००-६०,००० रुपये तक हो सकती है, अगर फिटमेंट फैक्टर २.२८-३.० अपनाया जाता है।ललर१व७लल७९९७ उदाहरण के तौर पर:

लेवल १ (क्लर्क): वर्तमान १८,००० + ऊ- फ नया ४१,०००-५४,००० रुपये।

लेवल १० (अफसर): वर्तमान ५६,१०० + ऊ- फनया १.२७-१.६८ लाख रुपये।

पेंशन में भी समान वृद्धि, कुल खर्च सरकार पर १.१५ लाख करोड़ रुपये सालाना बढ़ेगा।

हालांकि, यह वृद्धि प्रदर्शन मूल्यांकन पर निर्भर होगी। सातवें आयोग की तरह सालाना ३% इंक्रीमेंट के अलावा, अब -झ-ठ (एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट) में कोर्स पूर्णता को जोड़ा जाएगा।

प्रमोशन और वेतन वृद्धि के लिए 'परीक्षा' की नई शर्तें: कर्मयोगी पोर्टल का रोल

यहां सबसे बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। कार्मयोगी मिशन (मिशन कर्मयोगी) के तहत ळऋजढ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य कोर्स और लेवल-२ असेसमेंट (परीक्षा) को -झ-ठ से जोड़ा जा रहा है। (डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग) के ४ जुलाई २०२५ के आदेश के अनुसार, सभी केंद्रीय कर्मचारियों को सालाना कम से कम ५०% निर्धारित कोर्स पूरे करने होंगे, जिसमें कम से कम ६ कोर्स (डोमेन, बिहेवियरल और फंक्शनल स्किल्स पर) शामिल हैं

प्रमोशन के लिए: वरिष्ठता के बजाय स्किल-बेस्ड प्रमोशन पर जोर। ग्रुप -, इ और उ के लिए लेवल-वाइज कोर्स (जैसे ३ अनिवार्य कोर्स) पास करने जरूरी। रेलवे में ळ्ए नंबर ११७/२०२५ (११ नवंबर २०२५) के तहत यह -झ-ठ के पार्ट-२ में रिफ्लेक्ट होगा, जो प्रमोशन डीसीआर (Detailed Confidential Report) को प्रभावित करेगा।३५०

वेतन वृद्धि के लिए: सालाना इंक्रीमेंट प्रदर्शन-आधारित होगा। कोर्स फेल होने पर -झ-ठ स्कोर कम होगा, जिससे वेतन स्थगन या कम वृद्धि हो सकती है। २०२५-२६ -झ-ठ साइकल से लागू,

रेलवे, डिफेंस और अन्य मंत्रालयों में पहले से लागू हो चुका है, लेकिन आठवें आयोग में इसे पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बाध्यकारी बनाने पर विचार चल रहा है।ऑनलाइन कोर्स मुफ्त हैं, लेकिन १००% ऑनबोर्डिंग और प्रोफाइल अपडेट अनिवार्य।

उद्देश्य और चुनौतियां: क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

यह सुधार 'रूल-बेस्ड' से 'रोल-बेस्ड' क्ष्ठ मैनेजमेंट की ओर कदम है, जो कर्मचारियों को डिजिटल और स्किल्ड बनाएगा। लेकिन कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि यह अतिरिक्त बोझ है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी के कारण।आयोग की रिपोर्ट आने तक ये प्रस्ताव चर्चा का विषय हैं, लेकिन लागू होने पर लाखों कर्मचारियों की जिंदगी बदल सकती है।कर्मचारी संगठन आयोग से अपील कर रहे हैं कि परीक्षा को वैकल्पिक रखा जाए.

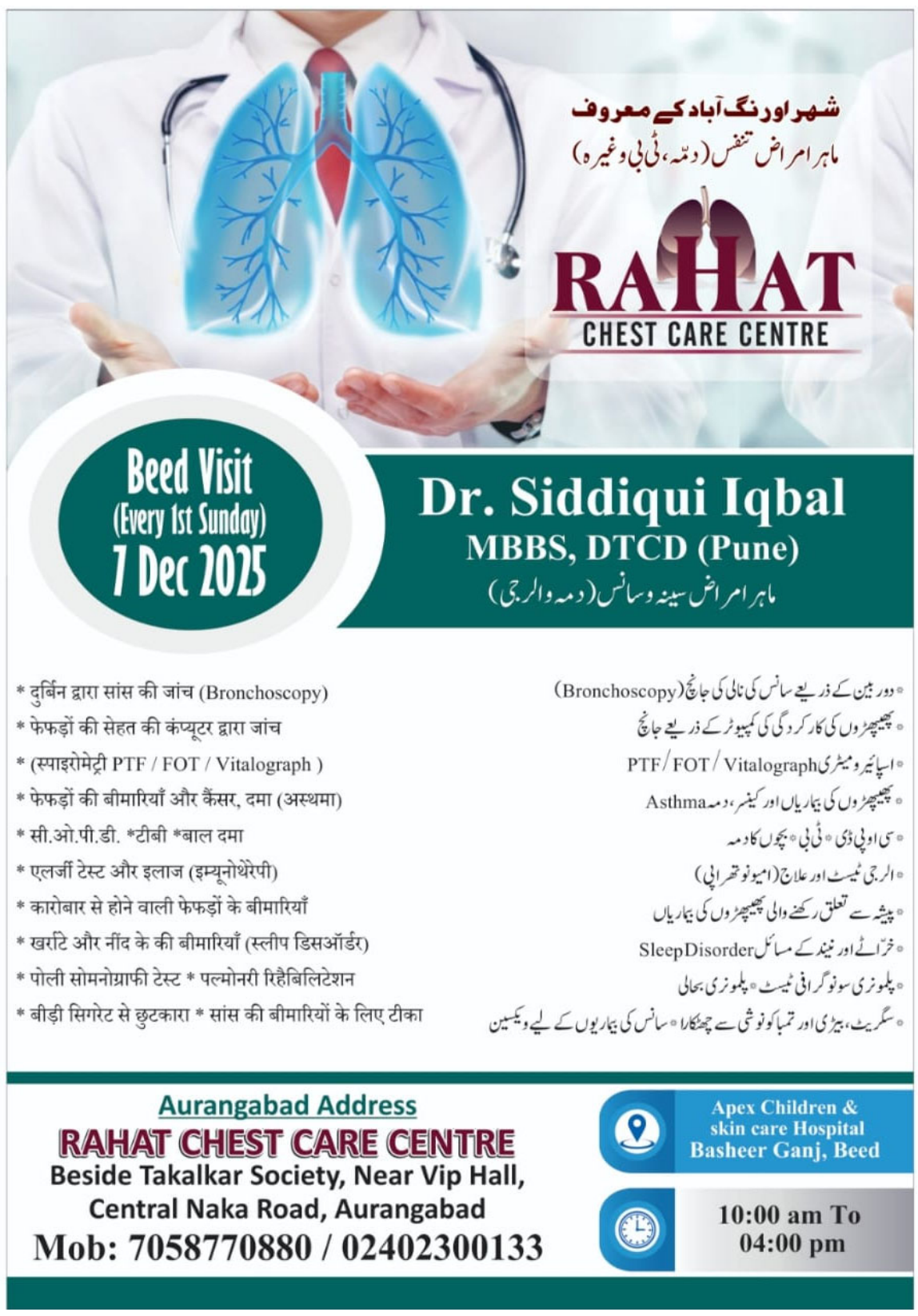

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

गेवराई नगर परिषद चुनाव में दो गुटों में तनाव, २१ लोगों पर केस दर्ज

सोशल मीडिया पर तनाव फैलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर, मतगणना के दिन उपद्रव करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी–पुलिस अधीक्षक

गेवराई (बीड), ६ दिसंबर (प्रतिनिधि)

२ दिसंबर २०२५ को हुई गेवराई नगर परिषद की सार्वत्रिक चुनाव की मतदान प्रक्रिया के दौरान प्रभाग क्रमांक १० (जिल्हा परिषद उर्दू स्कूल के पास) में दो राजनीतिक गुटों के बीच छोटा-सा विवाद हुआ था। यह विवाद बाद में बढ़ गया और दोनों पक्षों ने अवैध रूप से लोग इकट्ठा कर एक-दूसरे पर मारपीट व गाली-गलौज की।

एक गुट ने कृष्णाई बंगले के कंपाउंड में घुसकर वहाँ मौजूद लोगों पर हमला किया। जवाब में दूसरे गुट ने कोल्हेर रोड स्थित जिल्हा परिषद बालक विद्यालय में पहुँचकर फिर हंगामा किया और पथराव कर एक चार पहिया वाहन के शीशे तोड़ दिए।

इस पूरे मामले में गेवराई पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक ७१२/२०२५ के तहत भारतीय न्याय संहिता २०२३ की धारा २२३, १८९(२) एवं अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत कुल २१ नामजद व २०-३० अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

पुलिस जांच में अब तक १७ आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्हें नोटिस देकर छोड़ा गया है। सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जाँच से २० और आरोपियों की शिनाख्त हो चुकी है। जल्द ही उन्हें भी उनकी गिरफ्तारी कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गिरफ्तार आरोपियों से कड़ी पूछताछ की गई है और सभी को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट व अपर पुलिस अधीक्षक, बीड के सामने पेश कर अच्छे आचरण का बंधपत्र व भारी जुर्माना राशि का बॉन्ड भरवाया जा रहा है। भविष्य में कोई गैर-कानूनी हरकत करने पर भारी जुर्माना या जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी, ऐसा सख्त इशारा पुलिस ने दिया है।

पुलिस अधीक्षक नवनीत कावत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आगामी मतगणना के दिन अगर कोई भी व्यक्ति कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोश कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, यहाँ तक कि उसे तड़ीपार भी किया जा सकता है।साथ ही बीड पुलिस ने शहरवासियों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसा पोस्ट, वीडियो या मैसेज न करें जिससे धार्मिक, जातीय या सामाजिक तनाव पैदा हो। सायबर सेल लगातार नजर रखे हुए है और दोषियों पर तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी।

शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार करे

विधायक संदीप क्षीरसागरने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री से की लिखित मांग

बीड, ६ दिसंबर (प्रतिनिधि)

महाराष्ट्र भर के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों, मुख्याध्यापकों, संस्था चालकों तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न जायज मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ रखा है। इस आंदोलन को देखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गट) के विधायक संदीप क्षीरसागर ने राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करते हुए सभी मांगें मानने की लिखित मांग की है।

श्री क्षीरसागर ने कहा कि शिक्षक समाज का मार्गदर्शक घटक हैं। उनके साथ संवेदनशील और सकारात्मक रुख अपनाते हुए सरकार को उनकी मांगों का तुरंत निराकरण करना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा शालेय शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे को अलग-अलग पत्र लिखे हैं।

शिक्षकों-कर्मचारियों की प्रमुख मांगें जिन्हें लेकर आंदोलन चल रहा है:

सर्वोच्च न्यायालय के टीईटी अनिवार्यता संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार याचिका दाखल की जाए

शिक्षण सेवक योजना पूरी तरह रद्द कर सभी को नियमित वेतन श्रेणी लागू की जाए

अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह शिक्षकों को भी १०, २० व ३० वर्ष की सेवा के बाद संशोधित तीन वेतन लाभ वाली आश्वासित प्रगति योजना दी जाए

१५ मार्च २०२४ का संचमान्यता (Staff -pproval) संबंधी शासन निर्णय तत्काल रद्द किया जाए

लंबे समय से बंद शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की भर्ती तुरंत शुरू की जाए

विषय स्नातक शिक्षकों को बिना भेदभाव के स्नातक वेतन श्रेणी का लाभ दिया जाए

इन मांगों को लेकर प्रदेश भर में ५ दिसंबर (शनिवार) को ज्यादातर स्कूल-कॉलेज बंद रखे गए। शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी पिछले कई दिनों से विभिन्न माध्यमों से आंदोलन कर रहे हैं।

विधायक संदीप क्षीरसागर ने कहा, शिक्षक राष्ट्र-निर्माता हैं। उनके साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार को बिना देरी किए उनकी सभी जायज मांगें माननी चाहिए। आंदोलन अभी भी जारी है और शिक्षक संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर सुप्रिया सुले ने चैत्यभूमि में दी श्रद्धांजलि

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं सांसद सुप्रिया सुले ने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के ६९वें महापरिनिर्वाण दिवस पर दादर स्थित चैत्यभूमि पहुंचकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे।

मीडिया से बातचीत में सुप्रिया सुले ने सवाल उठाया कि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के भव्य स्मारक के लिए इंदु मिल की जो जमीन दी गई थी, उसके बावजूद इस स्मारक के काम में इतनी देरी क्यों हो रही है? राज्य सरकार बड़े-बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तेजी से पूरी कर रही है, लेकिन करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र यह इंदु मिल स्मारक आखिर पूरा क्यों नहीं हो रहा? इसका जवाब राज्य सरकार को देना चाहिए।

सुप्रिया सुले ने आगे कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार के दौरान खुद केंद्र सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र में महिलाएं असुरक्षित हैं, हर दिन अपराध बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में बढ़ता अपराध-ग्राफ एक हकीकत है और ये केंद्र की ही रिपोर्ट है।

उन्होंने इंडिगो एयरलाइंस के मुद्दे पर भी केंद्र को घेरा। सुप्रिया सुले ने कहा, पिछले दो दिनों में हजारों यात्रियों को जो परेशानी उठानी पड़ी, वह बेहद चिंताजनक है। हमने यह मामला संसद में भी उठाया है। केंद्र सरकार को इंडिगो के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जो यात्री अभी परेशान हैं, उनके सवालों का जवाब भी केंद्र को देना होगा। इतने बड़े स्तर पर यह बदइंतजामी आखिर कैसे हुई? बिना कोई पूर्व सूचना दिए यह सब कैसे शुरू हो गया? इससे लोगों के करोड़ों रुपये और अनमोल समय बर्बाद हुआ।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा, केंद्र सरकार को चाहिए कि इंडिगो जैसी और पांच कंपनियां तैयार करे। साथ ही यह भी बताए कि इंडिगो की सेवा में अचानक क्या रुकावट आई? सिस्टम अचानक क्यों ठप हो गया? समस्या का समाधान क्या है? इन सभी सवालों के जवाब केंद्र सरकार को संसद में देना होंगे।

इंडिगो की सेवा अचानक क्यों हो गई ठप? केंद्र को संसद में जवाब देना होगा: सुप्रिया सुले

मेहरून, जलगांव में दर्दनाक त्रासदी! हाई-टेंशन करंट ने ली तीसरी मासूम जान भी

जलगांव (अकील ख़ान ब्यावली)

मुस्लिम बहुल घनी आबादी वाले क्षेत्र महरून में बीते दो दिनों से फैला मातम आज और गहरा हो गया, जब हाई-टेंशन करंट की भयावह चपेट में आई तीसरी मासूम शहिद फातिमा अज़ीम पठान, नायब इमाम मौलाना (स्व.) साबिर रज़ा बरकाती की भांजी, भी जीवन-मृत्यु के संघर्ष में पराजित होकर सुबह १२:३० बजे इस संसार से विदा हो गई। यह खबर शहर में बिजली की चमक की तरह फैल गई। वातावरण शोकाकुल हो उठा, आक्रोश और पीड़ा से भरा। लोगों के दिलों में एक ही प्रश्न,कब तक हमारी बस्तियाँ जनाज़ों के बोझ तले दबती रहेंगी? क्या जीवन की क़ीमत सिर्फ़ वादे हैं?

जनाज़े आँसू दहाड़ें हजारों लोगों की सिसकियां...पिछली रात नायब इमाम मौलाना साबिर रज़ा बरकाती और उनकी कम-सिन बेटी को रात्रि १० बजे हजारों शोकसंतप्तों की मौजूदगी में सुपुर्द-ए-ख़ाक किया गया।आज तीसरी मृत्यु ने पूरे मेहरून को पुनः शोक की गहरी अंधियारी में ढकेल दिया। यह वह परिवार था जो कुरआन के ज्ञान, शिक्षा के दीप और सुधार-ए-उम्मत की सेवा में निरंतर समर्पित था। उनकी विदाई एक युग के अवसान जैसी प्रतीत हुई।

जनता का रोष, प्रतिनिधि लामबंद! बिजली विभाग कटघरे में,त्रासदी के बाद सामाजिक-राजनीतिक प्रतिनिधि, फ़ारूक़ शेख, पूर्व कॉरपोरेटर रियाज़ बागबान, शेख यूसुफ़, मुख्तार शाह, इक़बाल वज़ीर इत्यादि ने बिजली विभाग के अधिकारियों को बुलाकर कड़े शब्दों में जवाब-तलब किया,

मुख्य मांगें: मृतकों के परिजनों को तत्काल उचित मुआवज़ा, हाई-टेंशन तारों की तत्काल मरम्मत एवं स्थानांतरण.स्थायी सुरक्षा उपाय. पिछले वर्षों के अधूरे वादों को लिखित

रूप में पूरा करने की गारंटी.विभाग ने २०-२० हज़ार रुपये की तात्कालिक सहायता तथा प्रति मृतक ४ लाख रुपये दो माह में देने का आश्वासन दिया। साथ ही ८ दिसंबर से हाई-टेंशन लाइन के कार्य आरंभ कराने का लिखित वचन भी दिया गया.फारूक़ शेख की सख़्त चेतावनी..

यदि ८ दिसंबर से कार्य आरंभ नहीं हुआ तो जनता सड़क पर उतरेगी,

हम नेशनल हाईवे जाम करेंगे!उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला हाई कोर्ट में ले जाया जायेगा.

सन् २०१७ की भयावह स्मृति .. अधूरे वादों का इतिहास

यह हादसा नया नहीं।

ठीक २०१७ में इसी क्षेत्र में टूटे हाई-टेंशन तारों ने दो युवा रिक्शाचालकों , इमरान खान और इमरान शेख ,की जान ले ली थी।

उस समय भी बिजली विभाग और जिला प्रशासन ने वादे किए थे परन्तु वादे, वादे ही रह गए

आज वही इतिहास पुनः खून से लिखा गया

मूलभूत समस्याएं , नेतृत्व मौन क्यों? न उचित सड़कें

न समय पर सफाई

न सार्वजनिक उद्यान

न सामुदायिक भवन

पूरे शहर की सड़कें बन गईं, मगर मेहरून आज भी गड्ढों की बस्ती बना हुआ है.जनता का प्रश्न तीखा है,क्या हमारा इलाक़ा सिर्फ़ चुनावी भाषणों के लिए है? विकास कब मिलेगा?

जनप्रतिनिधि की तत्परता,

क्षेत्र के विधायक राजू मामा भोळे ने मौलाना साबिर रज़ा के परिवार को १ लाख रुपये सहायता देने की घोषणा उनके प्रतिनिधि प्रशांत भाऊ के माध्यम से की.

तलवाड़ा में गूँजी गंगा-जमुनी तहज़ीब की पुकार

हज़रत टिपू सुल्तान जयंती में भागवत तावरे ने सरकार पर साधा निशाना, अदानी-अंबानी को ज़मीन देने का लगाया आरोप

तलवाड़ा प्रतिनिधि

देश भर की ९६ लाख एकड़ वक्फ ज़मीन पर सरकारी नज़र है और मुस्लिम द्वेष को जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है। वक्फ की ज़मीनें बचेंगी, यह उम्मीद हर स्तर पर बढ़ानी होगी, वरना अदानी-अंबानी के गले उतारने के लिए सरकार बड़े-बड़े भूखंड तैयार कर देगी। दर्गाहों और वक्फ संपत्तियों की रजिस्ट्री के नाम पर इतनी जटिल प्रक्रिया रखी गई है कि उससे मुस्लिम-विरोधी माहौल बनाया जा रहा है और सरकारी तंत्र समाज में तनाव पैदा कर रहा है। यह तीखा आरोप प्रसिद्ध समाजसेवी एवं वक्ता भागवत तावरे ने लगाया। वे तलवाड़ा में आयोजित हज़रत टिपू सुल्तान जयंती समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में हिंदू-मुस्लिम भाइयों की अभूतपूर्व भीड़ उपस्थित थी और गोदा-काठी गंगा-जमुनी तहज़ीब का ज़बरदस्त नज़ारा दिखा।

हज़रत टिपू सुल्तान जयंती के मौके पर भागवत तावरे ने अपने ओजस्वी भाषण में चौतरफा प्रहार किए। कभी युवाओं को अंतर्मुख किया, कभी सत्ताधारी राजनीति को आईना दिखाया। हज़रत टिपू सुल्तान और इब्राहिम गार्दी जैसे उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने देश की आज़ादी और निर्माण में अपना खून-पसीना बहाया है, फिर भी सिर्फ़ वोटों के समीकरण के लिए मुस्लिम द्वेष को बार-बार हवा दी जा रही है।

युवाओं से अपील करते हुए तावरे ने कहा, पढ़ो, आगे बढ़ो और हर तरह के नशे से दूर रहो। साथ ही चुनावी व्यवस्था पर तंज कसते हुए बोले, वोट की ताकत को पहचानो, नहीं तो सत्ता आपको बाँटती रहेगी। अंत में उन्होंने जोर देकर कहा, स्वस्थ लोकतंत्र और रचनात्मक समाज के लिए हमारा आपसी भाईचारा और एकता बरकरार रखनी होगी।

इस अवसर पर हज़रत टिपू सुल्तान के जीवन और संघर्ष पर विस्तार से प्रकाश डाला पूर्व जिला परिषद सदस्य एड. सुरेश हाते ने। संचालन गणपत नाटकर, पूर्व पंचायत समिति सदस्य शाम कुंड, दादाराव रोकड़े, शहेनशाह सौदागर, रवी मरकड, नजीर कुरैशी सहित कई गणमान्य नागरिकों ने अपने विचार रखे।

मंच पर डॉ. आसाराम मराठे, जयंती अध्यक्ष आक्रम सौदागर, किरण वावरे, पत्रकार आल्ताफ कुरैशी, पत्रकार नदीम शेख, डॉ. सिराज आरजु, डॉ. सुरेश गांधले आदि प्रमुख लोग उपस्थित थे।

कार्यक्रम का सूत्रसंचालन दादाराव रोकड़े तथा प्रस्तावना जयंती उपाध्यक्ष रवी मरकड ने की। आभार प्रदर्शन ऋषी करडे ने किया।

चौखट : टिपू सुल्तान के बारे में फैलाई जा रही गलतफहमियाँ दूर करें - इरफान बागवान

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे टिपू युवा मंच के संस्थापक इरफान बागवान ने कहा, हज़रत टिपू सुल्तान के राज्य में हिंदू-मुस्लिम पूरी एकता और भाईचारे से रहते थे। उन पर हिंदू-विरोधी होने का आरोप सिर्फ़ धार्मिक द्वेष और राजनीतिक स्वार्थ के लिए लगाया जाता है। उन्होंने घोषणा की कि टिपू युवा मंच पूरे राज्य में घूम-घूमकर सामाजिक एकता को मज़बूत करेगा और यह संदेश पहुँचाएगा कि टिपू सुल्तान सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाले जन-नेता और दूरदर्शी शासक थे।

तलवाड़ा का यह आयोजन गंगा-जमुनी तहज़ीब की मिसाल बन गया जहाँ सैकड़ों हिंदू-मुस्लिम भाई एक मंच पर एक साथ खड़े होकर एकता का संदेश दे रहे थे।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com